Government of Rajasthan
Department of Information Technology & Communication
List of Total Announcements (as on 07/09/2012)
Financial Year 2012-2013

S.No.	Para No Part No Sub Para No	Main Description	Action Taken	Status
1	155 0 0	सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) हेतु आधारभूत संरचना के विकास में निरंतर प्रगति करते हुए हमारा प्रदेश राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत स्टेट डाटा सेंटर स्थापित करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न सेवायें ऑन-लाइन उपलब्ध करवाने हेतु ई-मित्र व सीएससी नेटवर्क में निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। इस परियोजना के माध्यम से प्रदत्त सेवाओं में मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हैसियत व आय प्रमाण पत्र, परिवहन निगम की टिकिटों की बिक्री एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं इत्यादि से संबंधित विभिन्न सेवायें शामिल हैं। सुगम एकल खिड़की के माध्यम से अब तक इस वर्ष लगभग 26 लाख लोगों को विभिन्न सेवायें प्रदान की गई हैं।	सूचनात्मक हैं ।	Action Not Required
2	156 0 0	नागरिकों को विभिन्न सेवायें उपलब्ध करवाने में कॉल सेंटर एक महत्त्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुआ है। वर्तमान में अनेक राजकीय विभागों एवं राजकीय उपक्रमों ने अपने कॉल सेंटर स्थापित कर रखे हैं। मैं यह घोषणा करता हूँ कि आगामी वर्ष एक एकीकृत कॉल सेंटर की स्थापना की जायेगी जिसके द्वारा विभिन्न विभागों की सेवायें एक ही टेलीफोन नंबर के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।	यह परियोजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी थी। भारत सरकार से वित्तीय सहमति में देरी को दृष्टिगत रखते हुए वित्त विभाग द्वारा इस हेतु राज्य आयोजना मद से बजट उपलब्ध कराने की सैद्धान्तिक सहमति दिनांक 16-07-12 को प्रदान की गयी है। अब इस परियोजना हेतु भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के लिये मना कर दिया गया है। अतः परियोजना हेतु राज्य सरकार से पूर्ण वित्तीय सहायाता हेतु सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर कॉल सेन्टर स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी।	Under Progress
3	157 0 0	राज्य में I.T. की सहायता से विभिन्न विभागों की अनेक योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। साथ ही, I.T. विभाग को सुदृढ़ करने की दृष्टि	• वित्त विभाग के अनुमोदन के पश्चात दिनांक 17-07-2012 को प्रोग्रामर के 248 पद (ब्लॉक मुख्यालय हेतु), सूचना सहायक के	Under Progress

S.No.	Para No Part No Sub Para No	Main Description	Action Taken	Status
		से तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर तकनीकी अधिकारी एवं कर्मचारियों के 750 पद सृजित किये जायेंगे।	287 पद (तहसील मुख्यालय हेतु) एवं लेखाकर के 33 पद (जिला मुख्यालय हेतु) कुल 568 पद सृजित करने के आदेश जारी कर दिये गये है। मुख्यालय हेतु इसी बजट घोषणा के अन्तर्गत शेष् 23 पदों हेतु पत्रावली वित्त विभाग में सहमति हेतु प्रक्रियाधीन है। • प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक के पदों के लिए नियम में संशोधन प्रस्तावित है जिसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रशासनिक स्वीकृति के पश्चात नियमों में परिर्वतन की कार्यवाही कर कार्मिक विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है एवं आगे की कार्यवाही हेतु पत्रावली RPSC को भेज दी गयी है।	
4	158 0 0	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कार्यालयों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान सचिवालय में प्रायोगिक तौर (experimental basis) पर बायोमैट्रिक प्रणाली लागू की गई है। यह व्यवस्था चरणबद्ध रूप से सचिवालय के साथ-साथ जिला कलक्टर कार्यालयों एवं अन्य राजकीय कार्यालयों में लागू की जायेगी।	दिनांक 16.04.2012 से बायोमैट्रिक उपस्थिति तंत्र सचिवालय एवं समस्त जिला कलेक्टर कार्यालयो में क्रियान्वित कर दिया गया है। विभाग द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जा रहा है तथा अतिरिक्त हार्डवेयर भी स्थापित किया जा रहा है। रूपये 106.00 लाख की परियोजना SeMT द्वारा अनुमोदित कर दी गयी है। माह नवम्बर 2012 तक परियोजना पूर्णत: क्रियाशील कर दी जायेगी।	Under Progress